

दिल्ली के अस्पताल से मांगा अंडरटैकल
कैदी हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार, 48 घंटे में फ्राइम बांध ने दबोचा

नई दिल्ली। दिल्ली जेल प्रॉच की सेंट्रल रेंज टीम ने अस्पताल से भागे एक अंडरटैकल कैदी को मात्र 48 घंटे के अंदर हिमाचल प्रदेश के जना गिले से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि फवन भाड़ा (26 वर्ष) नामक आरोपी ने सेंट्रल के सेंट्रल जेल में बानबुलकर अज्ञात पदार्थ खाकर खुद को बीमार दिखाया। इसके बाद उसे डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल और बाद में इलाज के लिए जेलों का अस्पताल रेफर किया गया। 26 जून की रात करीब 6-45 बजे आरोपी ने बंधनभंग जाने की अनुमति मांगी और वेंटिलेशन होल से भाग निकला। इस घटना के बाद अंडरटैक एस्टेट थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 262 के तहत मामला दर्ज किया गया था इसके बाद महिपाल सिंह के नेतृत्व में बनी विशेष टीम ने (एसपी सीटी मोहन के पर्यवेक्षण में) तकनीकी निगरानी, मनवीय सुविधा जानकारी और फील्ड ऑपरेशन के जरिए तुरंत तलाश शुरू की।

जनकपुरी में 3 साल की मासूम से रेप के आरोपी की जमानत रद्द, दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला



नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ हुए यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा एक बड़ा और सख्त फैसला सुनाया गया है। अदालत ने इस जघन्य अपराध के आरोपी 57 वर्षीय स्कूल कर्मचारी की जमानत रद्द कर दी है। हाईकोर्ट द्वारा आरोपी को 1 जुलाई को दोपहर 2 बजे तक संबंधित POC SO (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर्म सेक्सुअल ऑफेंसेस) कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने का सख्त निर्देश दिया गया है। यह फैसला दिल्ली पुलिस और पीडित बच्ची की मां द्वारा आरोपी की जमानत के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए लिया गया है। गौरतलब है कि निचली (ट्रायल) अदालत द्वारा 7 मई को आरोपी को जमानत दे दी गई थी, जिसे अब उच्च न्यायालय द्वारा सिरि से खारिज कर दिया गया है। पुलिस शिकायत के अनुसार, यह झकझोर देने वाली वारदात 30 अप्रैल को घटी थी। पीडित बच्ची की मां द्वारा जनकपुरी थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में बताया गया था कि स्कूल में दाखिला होने के महज दूसरे दिन ही स्कूल परिसर के दौरान बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न किया गया। आरोपी उसी निजी स्कूल में काम करने वाला 57 वर्षीय कर्मचारी है। इस मामले में पुलिस द्वारा लविरित कार्रवाई करते हुए आरोपी कर्मचारी को 1 मई को ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। बीच में उसे जमानत मिल गई थी, लेकिन अब हाईकोर्ट के इस ताजा आदेश के बाद आरोपी को वापस जेल जाना होगा। इस संवेदनशील मामले की आगे की कानूनी कार्यवाही अब सीधे POC SO कोर्ट में चलेगी।

30 जून से दिल्ली में एसआईआर की दस्तक, बीएलओ पहुंचेंगे घर-घर; 7 अक्टूबर को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट

नई दिल्ली। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आने वाले दिनों में आपके दरवाजे पर चुनाव आयोग की घंटी बज सकती है। दिल्ली में वोटर लिस्ट (मतदाता सूची) को पूरी तरह अपडेट करने के लिए चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटीसिव रिवीजन (एसआईआर) की शुरुआत कर दी है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) अशोक कुमार के मुताबिक, पूरे 21 साल बाद दिल्ली में इतने बड़े स्तर पर यह खास अभियान चलाया जा रहा है।

अगर आपका अभी तक वोटर आईडी नहीं बना है, या उसमें कोई गलती है, तो आपके पास इसे ठीक कराने का यह सबसे बेहतरीन मौका है। दिल्ली में लगभग 13 हजार बूथ

लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) 30 जून से घर-घर जाकर वेरिफिकेशन का काम शुरू करेंगे। अगर आप पहली बार में घर पर नहीं मिलते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि टीम आपके घर कम से कम 3 बार विजिट करेगी। मिलेगा न्यूमिशन फॉर्म - सर्वे के दौरान आपको दो न्यूमिशन फॉर्म दिए जाएंगे। एक फॉर्म आपको भरकर बीएलओ को देना होगा और दूसरा अपने पास संभालकर रखना होगा।

दस्तावेजों का इंसुट नहीं- इस फॉर्म को जमा करते समय आपको किसी भी अन्य डॉक्यूमेंट या आईडी फ्रॉफ की फोटोकॉपी देने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन भी है सुविधा- यदि आप काम के सिलसिले में घर से

बाहर रहते हैं या शहरी इलाके में हैं, तो आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भी भर सकते हैं। इसका मकसद उन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाना है जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो अब दिल्ली छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, ताकि फर्जी वोटिंग को रोका जा सके। साथ ही, 18 साल की उम्र पूरी कर चुके नए युवाओं के नाम जोड़े जाएंगे। वोटर लिस्ट में सुधार और नए नाम जोड़ने का पूरा कार्यक्रम इस प्रकार तय किया गया है 30 जून घर-घर जाकर डोर-टू-डोर सर्वे और वेरिफिकेशन की शुरुआत।

5 आगस्त वोटर लिस्ट के पहले ड्राफ्ट (प्रारूप) का प्रकाशन। 7 अक्टूबर सभी सुधारों और दावों के

निपटारे के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। इससे पहले दिल्ली में इस स्तर का स्पेशल रिवीजन साल 2002-2004 में हुआ था। चुनाव आयोग ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए साल 2002 की पुरानी वोटर लिस्ट को भी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है ताकि लोग पुरानी डिटेल्स भी चेक कर सकें। इसके अलावा, चुनाव आयोग पोलिंग बूथ्स को भी व्यवस्थित कर रहा है और अब एक पोलिंग स्टेशन पर अधिकतम 1,200 से यादा वोटर्स नहीं होंगे, जिससे वोटिंग के दिन लंबी लाइनों से राहत मिलेगी। जनता की मदद के लिए दिल्ली के सभी जिलों में जल्द ही विशेष कैप और हेल्पडेस्क भी लगाए जाएंगे।

तकनीकी खराबी से वायलेट लाइन पर सेवा बाधित, बढ़ी परेशानी

दिल्ली मेट्रो की वायलेट लाइन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। तकनीकी खराबी के चलते वायलेट लाइन पर सेवा बाधित हुई है। इससे मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ लगी हुई है। यात्रियों को अन्य लाइन्स इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। कश्मीर गेट से राजा नाहर सिंह बसभण्डा रूट वाली वायलेट लाइन में तकनीकी खराबी की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि दिल्ली मेट्रो के ताजा अपडेट की मुताबिक सेवाओं को सामान्य रूप से दोबारा शुरू कर दिया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट के

माध्यम से दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने इस बात की जानकारी दी है। फिलहाल सेवाएं शुरू होने के बाद यात्रियों ने रहत की सांस ली है। दिल्ली मेट्रो ने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए बताया कि सेंट्रल सेक्टेरिएट मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन सेवाओं में देरी हो रही है। अन्य सभी लाइनों पर सेवाएं सामान्य हैं। बता दें कि कश्मीर गेट से यात्री स्टेशन पर ट्रेन के चलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन खराबी की वजह से हुई देरी ने यात्रियों को मुसीबत में डाल दिया। मेट्रो

कॉर्पोरेशन ने 9 बजकर 17 मिनट पर सिग्नल में खराबी की जानकारी दी थी। हालांकि 12 मिनट बाद इस रूट पर सेवाएं फिर शुरू कर दी गईं लगभग 20 मिनट यात्रियों को दिक्कत हुई। इस बीच दिल्ली मेट्रो की तरफ से अन्य लाइनों से यात्रा करने की सलाह दी गई थी। तकनीकी खराबी के कारण देखते ही देखते यात्रियों की भारी भीड़ से सेंट्रल सेक्टेरिएट मेट्रो स्टेशन खराब-खराब भर गया। हालांकि अन्य मेट्रो स्टेशनों पर भीड़ का यह हाल दिखाई दिया। मेट्रो स्टॉफ द्वारा यात्रियों से संयम बरतने की अपील की गई।

असम बाढ़ पर अमित शाह ने सीएम हिमंत बिस्वा सरमा से की बात

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा से फोन पर बात कर राय के कुछ हिस्सों में उत्पन्न बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली।

अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, शाह ने राय की उपनती नदियों के कारण हुए किसी तरह के सर्भावित नुकसान के बारे में जानकारी ली और स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया। असम राय आपदा प्रबंधन

प्राधिकरण (एसडीएमए) के अनुसार, घेमाजी जिले के चार राजस्व सर्किल के 69 गांवों में लगभग 16,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री शर्मा ने रविवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा था, घेमाजी में बाढ़ की स्थिति बनने के बाद से मैं हलात पर लगातार नजर रख रहा हूं। हमारे लोगों के जीवन पर इसके प्रभाव से हम बेहद दुखी हैं। इस कठिन समय में हम उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि राय सरकार प्रभावित परिवारों की तत्काल सुरक्षा

सुनिश्चित करने और उनके दीर्घकालिक पुनर्वास को प्राथमिकता देने के लिए अपने सभी संसाधन जुटा रहे हैं। शर्मा ने कहा, हम अपने लोगों पर इस बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इससे पहले, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (एनएफआर) के एक प्रवक्ता ने बताया था कि बाढ़ और कटाव से एक पुल प्रभावित होने के कारण घेमाजी जिले के आरचिपथार और सिमैन चापरी रेलखंड पर रेल परिचालन स्थगित कर दिया गया है।

कमीशनखोरी के जाल में फंसा राजधानी का स्वास्थ्य विभाग, रडार पर 100 डॉक्टर; अब ऊपर तक पहुंची जांच

दिल्ली। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में दवा एवं चिकित्सा उपकरणों की खरीद में हुए 650 करोड़ रुपये के कथित घोटाले की जांच अब शीर्ष प्रशासनिक स्तर तक पहुंच गई है। सूत्रों के अनुसार, 100 से अधिक डॉक्टरों, अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका जांच के दायरे में है। इनमें घोटाले के दौरान स्वास्थ्य विभाग में अहम पदों पर तैनात कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं। बताया जा रहा कि घोटाला पूरी तरह से कमीशनखोरी से जुड़ा है, जिसमें

वरिष्ठ अधिकारियों, कर्मचारियों व निजी लोगों को फायदा पहुंचाया गया। सूत्रों के अनुसार, एसीबी इस मामले की दो स्तरों पर जांच कर रही है। पहले स्तर पर स्वास्थ्य विभाग के प्रशासनिक निर्णयों, खरीद संबंधी मंजूरीयों और वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है, जबकि दूसरे स्तर पर केंद्रीय खरीद एजेंसी (सीपीए), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डीजीएचएस), डॉक्टरों और खरीद प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों की भूमिका की जांच की जा रही है।

पूर्व डीजीएचएस डॉ. वत्सला अग्रवाल, तत्कालीन हेड ऑफ ऑफिस डॉ. विनोद कुमार रंगा और डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स नीरज चोपड़ा की गिरफ्तारी के बाद अब जांच और तेज होगी। अब जांच एजेंसियां यह पता लगा रही हैं कि खरीद प्रस्तावों की मंजूरी, टेंडर प्रक्रिया, तकनीकी अनुमोदन और वित्तीय स्वीकृति के विभिन्न स्तरों पर किन-किन अधिकारियों की भूमिका रही। सूत्रों का कहना है कि घोटाले के दौरान स्वास्थ्य विभाग में तैनात कम से कम पांच से सात आईएएस

अधिकारियों से पूछताछ की तैयारी की जा रही है। जांच एजेंसियों का फोकस केवल टेंडर प्रक्रिया तक ही सीमित नहीं है। अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों से केंद्रीय खरीद एजेंसी (सीपीए) को भेजी गई दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और अन्य सामग्री की मांग का सीपीए की ओर से की गई वास्तविक खरीद से बारीकी से मिलान किया जा रहा है। एजेंसियां संबंधित अस्पतालों के मांग पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वितरण रिकॉर्ड और खरीद फाइलों का भी मिलान कर

रही हैं। जांच में कई महत्वपूर्ण खरीद से जुड़े दस्तावेज और मूल फाइलें गायब मिली हैं। गिरफ्तार पूर्व महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं (डीजीएचएस) डॉ. वत्सला अग्रवाल, पूर्व हेड ऑफ ऑफिस डॉ. विनोद कुमार रंगा और डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स नीरज चोपड़ा से पूछताछ में इन्हें पहलुओं पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जांच एजेंसी गायब रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, भुगतान संबंधी दस्तावेज की कड़ियां तलाश रही हैं। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि

स्वास्थ्य विभाग में तैनात कुछ वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों ने अपने स्तर पर पसंद के अधिकारियों और कर्मचारियों की महत्वपूर्ण पदों पर तैनाती कर खरीद व्यवस्था पर प्रभाव किया है। सीपीए और उससे जुड़े अहम पदों पर की गई इन तैनातियों का फायदा उठाकर निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया। यह पूरा मामला कमीशनखोरी के तहत चलाया गया है। 650 करोड़ रुपये के दवा एवं चिकित्सा उपकरण खरीद घोटाले में जांच का शिकंजा अब शीर्ष अधिकारियों तक पहुंच गया है।

बहुजन हिताय!



बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat.net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 230 ● नई दिल्ली ● मंगलवार 30 जून 2026 ● प्रभात कालीन

● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन

मजदूर संगठन
के सदस्य बनें

E-mail :

rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

10वीं के छात्रों के लिए बड़ा फैसला, बोर्ड ने जारी की तीन भाषा नीति की नई गाइडलाइन

नई दिल्ली। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने श्री-लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर बड़ा बदलाव किया है। बोर्ड की नई गाइडलाइंस के अनुसार मौजूदा 10वीं कक्षा के छात्रों को अब तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं देनी होगी। इस फैसले से लाखों छात्रों और अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। आइए समझते हैं नई गाइडलाइंस के बारे में विस्तार से। सीबीएसई की नई गाइडलाइंस के अनुसार मौजूदा कक्षा 10 के छात्रों पर यह नई त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। इसके अलावा कक्षा 7, 8 और 9 में पढ़ रहे मौजूदा छात्रों को आगे चलकर कक्षा 10 में तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं देनी होगी। जिन छात्रों ने पहले से दो विदेशी भाषाएं चुनी हैं, वे उन्हें जारी रख सकते हैं, लेकिन उनके साथ एक अतिरिक्त भारतीय भाषा पढ़ना भी जरूरी होगा। पाँचदस में सम्पूर्ण पूरी गाइडलाइंस सीबीएसई की नई श्री-लैंग्वेज पॉलिसी के अनुसार छात्रों को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी, जिनमें से कम से कम दो भाषाएं भारतीय भाषाएं होना जरूरी है। तीसरी भाषा के रूप में गैर-भारतीय भाषा भी चुनी जा



सकती है, लेकिन शर्त यह है कि बाकी दो भाषाएं भारतीय हों। कक्षा 10 (2026-27) के मौजूदा छात्रों के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्हें तीसरी भाषा की पढ़ाई या बोर्ड परीक्षा नहीं देनी होगी और वे पुराने सिस्टम के अनुसार ही पढ़ाई जारी रखेंगे। वहीं कक्षा 9 के सभी छात्रों को तीन भाषाएं पढ़ना अनिवार्य होगा। इनमें से कम से कम दो भारतीय भाषाएं होना जरूरी है, जबकि तीसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, अरबी या स्पेनिश जैसी गैर-भारतीय भाषा भी चुनी जा सकती है।

2026-27 से नई गाइडलाइंस लागू होंगी

सीबीएसई का मुख्य उद्देश्य छात्रों को कई भारतीय भाषाओं में दक्ष बनाना और भाषा सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना है, ताकि उनकी शिक्षा संतुलित और समग्र रूप से विकसित हो सके।

बोर्ड चाहता है कि भाषा सीखना केवल एक विषय न होकर एक सार्थक, रोचक और ज्ञानवर्धक अनुभव बने, जो छात्रों के सर्वांगीण विकास में मदद करे। इसके अलावा, सेकेंडरी स्टेज (कक्षा 9 और 10) में तीसरी भाषा को शामिल करना

मिडिल स्टेज (कक्षा 6 से 8) में शुरू हुई भाषा सीखने की प्रक्रिया का ही विस्तार है। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से सीबीएसई से जुड़े स्कूलों में भाषा नीति को लागू करने के लिए विस्तृत गाइडलाइंस जारी करना आवश्यक माना गया है।

कक्षा 9 के छात्रों के लिए श्री-लैंग्वेज पॉलिसी

स्थिति 1- अगर आप पहले से दो भारतीय भाषाएं पढ़ रहे हैं (जैसे हिंदी और तमिल), तो आप तीसरी भाषा के रूप में कोई दूसरी भारतीय भाषा या कोई गैर-भारतीय भाषा (जैसे अंग्रेजी या फ्रेंच) चुन सकते हैं।

स्थिति 2- अगर आप एक भारतीय और एक गैर-भारतीय भाषा पढ़ रहे हैं (जैसे तमिल और अंग्रेजी), तो आपको तीसरी भाषा के रूप में कोई भी भारतीय भाषा चुननी होगी।

स्थिति 3- अगर आप दो गैर-भारतीय भाषाएं पढ़ रहे हैं (जैसे अंग्रेजी और फ्रेंच), तो 2026-27 के लिए एक विशेष छूट दी जाएगी। आप इन्हें जारी रख सकते हैं, लेकिन आपको तीसरी भाषा के रूप में एक भारतीय भाषा जोड़नी अनिवार्य होगी।

डीएनडी फ्लाईओवर से यमुना में कूदा शख्स, गोताखोरों की टीम कर रही तलाश



नई दिल्ली। दिल्ली-नोएडा-दिल्ली फ्लाईओवर से एक शख्स ने यमुना नदी में छलांग लगा दी। सूचना पाकर एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर उसकी तलाश में जुट गई है। घटना 28 और 29 जून की देर रात की है। एनडीआरएफ प्रफुल कुमार ने कहा, इस घटना की जानकारी हमें कंट्रोल रूम के द्वारा मिली थी और लोकल पुलिस द्वारा ये जानकारी प्राप्त हुई कि देर रात करीब 2:30 बजे के आसपास की ये घटना है। कंट्रोल रूम से हमें सूचना करीब 3:25 बजे के आसपास मिली थी और हम लगभग 4 बजे यहाँ पहुंचे। तब से हमारा यहाँ बचाव-अभियान चल रहा है।

रणनीतिक साझेदारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेरोलस यात्रा भारत की पड़ोसी प्रथम और सागर नीति को नई मजबूती देने वाली मानी जा रही है। हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत ऐसा हिंद महासागर चाहता है जहां समुद्री सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि साथ-साथ आगे बढ़ें तथा देशों के बीच साझेदारी का आधार किसी का अक्षर या शक्ति नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और विश्वास हो। उनका यह संदेश केवल सेरोलस तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे हिंद महासागर क्षेत्र के लिए भारत की दीर्घकालिक रणनीति की भी दर्शाता है। सेरोलस के राष्ट्रपति पैट्रिक डॉमिंगो के साथ प्रतिनिधिगण्डल स्तर की बातों के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हिंद महासागर सभी देशों का साझा घर है और इसकी सुरक्षा, स्थिरता तथा समृद्धि सभी की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने ओशन ऑफ अपॉर्च्युनिटी अर्थात अवसरों का महासागर बनाने की परिकल्पना प्रस्तुत करते हुए कहा कि भारत इस क्षेत्र में विकास, सुरक्षा और सहयोग को समान महत्व देता है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों के लगभग सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा की। इनमें समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश, डिजिटल तकनीक, संपर्क व्यवस्था और ब्लू इकोनॉमी प्रमुख रहे। भारत ने सेरोलस के साथ अपने सफल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अनुभव साझा करने की भी घोषणा की। इससे सेरोलस में डिजिटल शासन, वित्तीय समावेशन और सार्वजनिक सेवाओं की अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिल सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेरोलस की सुरक्षा एक-दूसरे से जुड़ी हुई है। हिंद महासागर में समुद्री छत्कैती, अवैध मछली पकड़ना, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री आतंकवाद जैसे चुनौतियों से निपटने के लिए दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग लगातार मजबूत हुआ है। भारत लंबे समय से सेरोलस की समुद्री सुरक्षा क्षमता बढ़ाने में सहयोग करता रहा है। यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलु भारत द्वारा सेरोलस को मेड इन इंडिया फास्ट पेट्रोल वेल्स (एफवीबी) पीएस लेसम्बार सौंपना रहा। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित यह आधुनिक गश्ती पोत सेरोलस की तटरक्षक क्षमता को मजबूत करेगा। इसके साथ ही भारत ने डब्लू एम्बुलेंस, दस उपग्रहीय वाहन और पांच लेजर-निर्देशित नौकाएं भी सेरोलस को भेंट कीं। इन संसाधनों से सेरोलस को अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र की निगरानी, समुद्री गिरत और आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। हिंद महासागर आन वैश्विक व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग बन चुका है। दुनिया के ऊर्जा व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। ऐसे में इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना केवल भारत और सेरोलस ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए आवश्यक है। भारत लंबे समय से इस क्षेत्र में निर्यात-आधारित समुद्री व्यवस्था, स्वतंत्र नौहन और सभी देशों की संप्रभुता के सम्मान की वकालत करता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को इस यात्रा के दौरान सेरोलस का संबोधित विशेष राष्ट्रपति सम्मान गार्नियन ऑफ द ब्लू होराइनन भी प्रदान किया गया। उन्होंने यह सम्मान जलवायु परिवर्तन को चुनौतियों से संघर्ष कर रहे सभी देशों को समर्पित किया। यह सम्मान भारत और सेरोलस के बीच गहरे विश्वास तथा प्रधानमंत्री मोदी की हिंद महासागर क्षेत्र में सक्रिय भूमिका की अंतरराष्ट्रीय मान्यता के रूप में देखा जा रहा है। जलवायु परिवर्तन भी दोनों देशों के महयोग का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सेरोलस एक छोटा द्वीपीय राष्ट्र है, जो समुद्र के बढ़ते जलस्तर, तटीय कटाव और प्राकृतिक आपदाओं जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है। भारत अंतरराष्ट्रीय सीर मजबूतन, आपदा प्रतिक्रिया अवसररचना और ब्लू इकोनॉमी जैसी पहलों के माध्यम से ऐसे देशों को सहायता कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का यह संदेश कि समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत विकास सभी की साझा जिम्मेदारी है, इसी सोच को आगे बढ़ाता है। प्रधानमंत्री की यात्रा का एक सांस्कृतिक पक्ष भी रहा। उनके स्वागत में भारतीय और सेरोलस की सांस्कृतिक परंपराओं का सुंदर प्रदर्शन किया गया। विरोध रूप से गुजराने के कुछ क्षेत्र के पारंपरिक लोकनृत्य ने दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाया। प्रधानमंत्री ने सेरोलस के राष्ट्रीय जनसर्पित उद्घाान का भी दौरा किया और पर्यावरण संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। यह यात्रा ऐसे समय में हुई जब सेरोलस अपनी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इस पर्वण उत्पती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जो दोनों देशों के बीच विशेष संबंधों का प्रतीक है। भारत ने 1976 में सेरोलस को स्वतंत्रता के बाद से ही उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, क्षमता निर्माण तथा अवसररचना विकास जैसे क्षेत्रों में लगातार सहयोग दिया है। भू-राजनीतिक दृष्टि से भी यह यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हाल के वर्षों में हिंद महासागर क्षेत्र में विभिन्न वैश्विक शक्तियों की सक्रियता बढ़ी है। ऐसे समय में भारत छोटे द्वीपीय देशों के साथ समानता, विश्वास और पारस्परिक हितों पर आधारित संबंध विकसित कर रहा है। इसी क्षेत्र में संतुलन, स्थिरता और सहयोग की बढ़ावा मिलने की संभावना है। अंततः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेरोलस यात्रा केवल एक द्विपक्षीय दौरा नहीं, बल्कि भारत की व्यापक समुद्री और कूटनीतिक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अवसरों का महासागर को परिकल्पना यह संदेश देती है कि भविष्य की समृद्धि केवल आर्थिक विकास से नहीं, बल्कि सुरक्षित समुद्री मार्गों, पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल सहयोग और आपसी विश्वास से संभव होगा। भारत और सेरोलस की यह मजबूत होती साझेदारी हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।

ईंधन आपूर्ति और युद्ध की बदलती रणनीति

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध लगातार नए आयाम ले रहा है। शुरूआती दौर में जहां संघर्ष मुख्य रूप से जमीनी और हवाई सैन्य अभियानों तक सीमित था, वहीं अब दोनों देश एक-दूसरे की रणनीतिक अवसररचना को निशाना बना रहे हैं। विशेष रूप से यूक्रेन ने हाल के महीनों में रूस की तेल रिफाइनरियों और ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर ड्रोन हमलों की तीव्रता बढ़ा दी है। इन हमलों का असर अब रूस की घरेलू ईंधन आपूर्ति पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। स्वयं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्वीकार किया है कि देश के कई हिस्सों में ईंधन की कमी और पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। हाल ही में यूक्रेन ने रूस के दक्षिणी क्षेत्र क्रास्नोदर में स्थित स्लाव्यान्स्क-ना-कुबानी तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया। रूस के क्षेत्रीय प्रशासन के अनुसार, वायु रक्षा प्रणाली ने कई ड्रोन मार गिराए, लेकिन उनके मलबे से रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य चालू हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में रिफाइनरी से उड़ता धना काला धुआं दिखाई दिया, जिसने इस हमले की गंभीरता को दुनिया के सामने ता दिया। स्लाव्यान्स्क रिफाइनरी रूस की प्रमुख तेल प्रसंस्करण इकाइयों में से एक है। इसकी वार्षिक क्षमता लगभग 40 लाख टन कच्चे तेल को संसाधित करने की है। यहां से पब्लू ऑयल, नेफ्था और समुद्री ईंधन जैसे उत्पाद तैयार होकर काला सागर के बंदरगाहों के माध्यम से निर्यात किए जाते हैं। ऐसे में इस रिफाइनरी पर हमला केवल स्थानीय औद्योगिक क्षति नहीं, बल्कि रूस की ऊर्जा आपूर्ति और निर्यात क्षमता पर भी गंभीर प्रभाव डालता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेन्स्की ने यह भी दावा किया कि करोस्लाव क्षेत्र की एक अन्य रिफाइनरी को भी निशाना बनाया गया। यह क्षेत्र यूक्रेन की सीमा से लगभग 700 किलोमीटर दूर है। यदि यह दावा सही है, तो यह दर्शाता है कि यूक्रेन की लंबी दूरी तक मार करने वाली ड्रोन क्षमता लगातार विकसित हो

रही है। हालांकि रूसी अधिकारियों ने इस हमले की पुष्टि नहीं की, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने ड्रोन खतरों के कारण कई सड़कों को अस्थायी रूप से बंद करने की जानकारी दी। इन हमलों का सबसे बड़ा प्रभाव रूस की ईंधन आपूर्ति पर पड़ा है। राष्ट्रपति पुतिन ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में स्वीकार किया कि देश के कई क्षेत्रों में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए एक विशेष कार्यबल का गठन किया है, जो पूरे देश में ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। उन्होंने यह भी माना कि पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग रही हैं और परिवहन तथा व्यापार से जुड़े लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रूसी सरकार अब घरेलू मांग को प्राथमिकता देने के लिए डीजल निर्यात पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने पर भी विचार कर रही है। यदि ऐसा होता है, तो इसका असर केवल रूस तक सीमित नहीं रहेगा। यूरोप, एशिया और अन्य क्षेत्रों में कमी बाजार भी प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि रूस वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का एक प्रमुख स्रोत है।

निर्यात में कमी आने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतों में ज़ार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। यूक्रेन की रणनीति स्पष्ट दिखाई देती है। वह सीधे मोर्चे पर रूस की सैन्य शक्ति को चुनौती देने के साथ-साथ उसकी आर्थिक और औद्योगिक क्षमता को भी कमजोर करना चाहता है। तेल रिफाइनरियों पर हमले से रूस की सेना के लिए ईंधन उपलब्ध करना कठिन हो सकता है। इसके अलावा नागरिक परिवहन, उद्योग और कृषि क्षेत्र भी प्रभावित होते हैं, जिससे सरकार पर आर्थिक दबाव बढ़ता है। दूसरी ओर रूस का कहना है कि वह अपनी वायु रक्षा प्रणाली को और मजबूत कर रहा है तथा महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन लगातार हो रहे हमले यह संकेत देते हैं कि दुनिया विशाल भौगोलिक क्षेत्र में प्रत्येक ऊर्जा केंद्र को पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करना आसान नहीं है। यही कारण है कि युद्ध

अब केवल सीमा क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रूस के भीतर सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठान भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। ऊर्जा अवसररचना पर हमलों का असर आम नागरिकों पर भी पड़ता है। ईंधन की कमी से परिवहन महंगा होता है, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित होती है और महंगाई बढ़ सकती है। यदि पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता लगातार कम होती रही, तो रूस की अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। यही कारण है कि सरकार स्थिति को नियंत्रित करने के लिए निर्यात नीति और आपूर्ति प्रबंधन दोनों पर एक साथ काम कर रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है। वैश्विक ऊर्जा बाजार पहले ही भू-राजनैतिक तनाव, प्रतिबंधों और आपूर्ति संबंधी अनिश्चितताओं से प्रभावित है। ऐसे में रूस की रिफाइनरियों पर लगातार हमले तेल और गैस की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं। भारत जैसे ऊर्जा आयातक देशों के लिए भी यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कीमतों में किसी भी बड़े उतार-चढ़ाव का असर घरेलू अर्थव्यवस्था और महंगाई पर पड़ सकता है। अंततः यूक्रेन द्वारा रूस की तेल रिफाइनरियों पर किए जा रहे ड्रोन हमले यह दर्शाते हैं कि आधुनिक युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। अब जीत केवल सैनिकों की संख्या या हथियारों की क्षमता से तय नहीं होती, बल्कि ऊर्जा, आपूर्ति श्रृंखला, औद्योगिक ढांचे और आर्थिक स्थिरता भी युद्ध का महत्वपूर्ण मोर्चा बन चुके हैं।

रूस के सामने चुनौती केवल सैन्य जवाब देने की नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा व्यवस्था और घरेलू अर्थव्यवस्था को भी सुरक्षित रखने की है। वहीं यूक्रेन इन हमलों के माध्यम से रूस पर आर्थिक और मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाने की रणनीति अपनाए हुए है। आने वाले समय में यह ऊर्जा युद्ध रूस-यूक्रेन संघर्ष की दिशा और वैश्विक ऊर्जा बाजार दोनों को गहराई से प्रभावित कर सकता है।

फिर दूटा छात्रों का भरोसा

प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों या सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाओं की प्रतिस्पर्धी प्रकृति उम्मीदवारों पर दबाव बढ़ाती है जिससे कुछ उम्मीदवार अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए लोक हुए पत्रों का उपयोग करने जैसी अनेतिक प्रथाओं का सहारा लेते हैं।
अपर्याप्त नियामक निगरानी और प्रवर्तन तंत्र इस समस्या को और भी गंभीर बना देते हैं क्योंकि कमजोर दंड प्रभावी रूप से कदाचार को रोकने में विफल रहते हैं। वित्तीय प्रोत्साहन भी संगठित समूहों को कागजात लोक करने के लिए प्रेरित करते हैं क्योंकि वे लोक हुए कागजातों को प्रतिस्पर्धी बाजार में मूल्यवान वस्तु के रूप में देखते हैं।
जब तक परीक्षा तंत्र को पवित्र नहीं बनाया जाता, तब तक छात्रों के सपने टूटते रहेंगे और जिनदगियां खत्म होती रहेंगी। क्या छात्रों की आत्महत्याएं शासन व्यवस्था के लिए महज एक मौत का आंकड़ा ही बनी रहेगी।

मुद्दा- वास्तव में कैसा होगा हिंदू राष्ट्र?

इस सवाल का स्वतःस्पष्ट और तुरंत आने वाला उत्तर तो यहो होगा कि वर्तमान भारतीय राष्ट्र में सभी नागरिकों के लिए उन्मथ धर्म जाति वंशों की क्यों न हो, बराबरी की भी सविधान के जहिए गृहीती की गयी है उसकी जगह पर, हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं को अन्य धर्मों के लोगों के मुकाबले और खसमे पर मुसलमानों के मुकाबले, जो इस देश में सबसे बड़ अल्पसंख्यक समुदाय है, उन्मथ दंगे दिशा जाएगा। लेकिन, इस तरह की गैर-बराबरी को एक विशेष रूप से दमनकारी राज्य के भिन्न तो बताते नहीं रहा जा सकता है। वैसे तो वर्गीय-दमनकारी सम्मान में होकर राज ही दमनकारी होता है, लेकिन उस राज्य को जो इस तरह की असमानता को संस्थागत रूप देने का काम करेगा, उसे तो और भी खसमैर पर दमनकारी होने की जरूरत होगी। तब क्या हिंदू राष्ट्र का मतलब, सामूहिक रूप से हिंदुओं की तानशाही होगी, जिसे अन्य धर्मों को मानने वालों पर चलाया जाएगा। जैसा हो वह सफल उठथा जात है, फीरे ही जबाब अता हैइ “जी”। हिंदू राज में भी एक सिखावक तो सिखावकनहीं होखेगा, उसका धर्म चाहे जो भी क्यों न हो। हिंदू राज में एक चरमपंथी तो चरमपंथी ही रहेगा, उसका धर्म चाहे जो भी हो। हिंदू राज में एक गिग कन्ति रहे गिग कन्ति ही रहेगा, भले हो उसका धर्म कुछ

भी हो। इस तरह, तथकथित हिंदू राज हिंदुओं के बहुत की लोकिक नियंत्री में कोई बदलाव लेने का न तो कहर करता है और न ऐसा बदलाव लाएगा। लेकिन, तब स्वावल यह है कि इस तरह के राष्ट्र में अनिवार्य रूप से जो तानशाही का राज चल रहा होगा, वह किस के हितों को माधय रह होगा? इस सवाल का स्वतःस्पष्ट उत्तर है-इजारेदार पूंजी खात्री एकाधिकारवादी पूंजी के ही हित साथ रहा होगा। इसके नाम से जो उचित बनती है उसके विपरीत, एक हिंदू राज इजारेदार पूंजी की तानशाही के प्रिय और कुछ नहीं हो सकता है। बेरुक्त, ऐसे हिंदू राज में शासक्रीय अक्षेजनों पर हिंदू कर्मकांड और हिंदू धर्मिक अचर्यों का लेप चढ़था जाएगा। इसमें भी शक नहीं कि ऐसे राज में नैकरियों के लिए चयन में अन्त धर्मों के मानने कलों के मुकाबले हिंदुओं का विशेषता दी जाएगी। लेकिन, ऐसे राज में भी नवी नैकरियां तो न सिर्फ वैश्व ही वृत्तप होगी जैसा कि आज वृत्तप है बल्कि कारपोरेटी के कृत्रिम पंथा (एजेंड) को उत्थोग में लाने के चलते, आज जो नैकरिया है भी, उनमें से बहुत सी गायब हो जाएंगी। इस तरह, इसमें शक नहीं कि ऐसे राज में मुसलमानों को तथा अन्य अल्पसंख्यक धर्मिक समुहों के लोगों को बहुत भारी तथा बहुतरास्यी उपेक्षितों की ड्रेजन

पड़ेगा, लेकिन ऐसे राज में हिंदुओं को भी अपनी पीछ में कोई कमी महसूस करने का मौक़ा नहीं मिलेगा। दूसरी ओर, एक वर्ग जिसकी तकत ऐसे राज में बहुत बड़ जाएगी, वह है इजारेदार पूंजीपति वर्ग। और इस वर्ग के अंदर भी इजारेदार पूंजीपतियों के नये समूह की तकत विशेष रूप से बड़ जाएगी। दूसरे शब्दों में हिंदू राज एक ऐसा राज होगा जिसमें आम तौर पर बड़े भारतीय कारपोरेट राज करेगे और खासतौर पर अक्षेत्रीय और अन्धकारियों का राज होगा। यह 1930 के दशक के जर्मनी की यह दिलाता है। वहां भी नज़रियों का जवाब यही था कि वे “गैर-अर्थ” अन्धकारिहो, जैसा यूरपिय (नज़रियों का मानना था कि कोई जर्जि “आर्थ यूरपी” तो हो ही नहीं सकता थ) और नज़रियों का बंजारो (उसी तरह से नज़रियों के शिखर से “आर्थ नज़रियों” भी हो ही नहीं सकता थ) का उधेपुन करने के ज़रिए, “ आर्थ क्रेडता” को स्थापित कर रहे थे। बहरहाल, जर्मनी राज कोई “अर्थ राज” नहीं था। इस राज ने जो तानशाही कायम की थी, 1935 में ही कम्युनिस्ट इंटरनैशनल की मातवी कक्षिय में, उसके अस्थाज नज़रि दिग्गजों के संभवित के कटवी में- “वित्तीय पूंजी के सबसे प्रतिक्रियावादी, उससे संकीर्णकवादी और उससे साक्षात्कारही उत्तरी की खुदमस्तकुल अंतर्की तानशाही थी।” किसी राज

की पहचान उसे जताने कालों की पहचान से करना, कोई जरूरी नहीं है कि उस राज की सच्ची पहचान करता हो। फूडो जगह असली सवाल यह होत है कि वह कौन सा वर्ग है जो अपने ही स्वार्थों को आगे बढ़ाने के लिए संघर्षित राज का इस्तेमाल करता है। और आज के ज़माने में जिने भी राज किसी खास एथनिक या धर्मिक या भाषणी समूह के हितों को आगे बढ़ाने का दावा करते है और इजारेदार पूंजी जनतंत्र के पर करते है तथा अन्य समुदायों को दूसरे दर्जे के नागरिक बनाकर रखते है, कामरेव में इजारेदार पूंजी के ही स्वार्थों को आगे बढ़ते है। वे ऐसा करते है इजारेदार पूंजी की तानशाही कायम करने और एथनिक, धर्मिक या भाषणी आधार पर मेहनतकर जनता को बंटने के जहिए। एक आधुनिक, बहु-समुदायिक समाज में, किसी एक समुदाय या समूह का राज धोष जना, वास्तव में इजारेदार पूंजी की तानशाही घोष जना ही होता है। यह समेत किया जा सकता है कि अक्षिखर, उत्थम “धर्मनिरपेक्ष” राज में भी तो इजारेदार पूंजी का ही केलाकात होत है। तब इजारेदार पूंजी को अपनी तानशाही के मूर्त रूप के तौर पर एक ऐसे नये तथ्य पूरी तरह से मिल, हिंदू-शेकनकवादी राज की और इसीलिए ऐसे राज के कायम होने में धट्ट करने की जरूरत ही अथ है?

जौहर है कि इस तरह के बदलाव की जरूरत तभी होती है, जब राज्य के पहले काले रूप के लिए गंभीर खतरा पैदा हो जात है। और यह होता है ऐसे दौर है जब अर्थव्यवस्था गलबगंठ की शिखर हो जाती है और बेरोजगारी बहुत बड़ जाती है। हिंदू राज के ज़म पर, इस समय इजारेदार पूंजी की तानशाही को दिखा में जो आगे बड़ जा रहा है, नय-उदरवादी निजाम के बंद गली में जा फंसने को ही दिखाता है, जहां यह निजाम अर्थव्यवस्था में गलबगंठ तथा बड़ो हुई बेरोजगारी ले अथ है और मेहनतकर जनता को विश्वास संस्था के लिए, भारी बड़लाती लाश है। जनतंत्र, मेहनतकर जनता को प्रसिरोध और संघर्ष करने के लिए ज़्यादा मुंखदय देत है। इपेसिएर, संसट के होक दौर में, जनतंत्र को कतारने को कोशिश की जाती है। इसका मकसद होता है इजारेदार पूंजी के वचकंव के लिए खतरों पर अंकुश लगाकर रखना लेकिन, जहां संसट लंबा चल रहा हो और उसके वचकंव के लिए खतरा लगातार बना रहे, तो इजारेदार पूंजी और इजारेदार अतिवादी कदम उठ लेते है। अब वह ऐसा किसी भी ताकत के साथ मतडोख कर लेती है, जो जनता को बंटने में सक्ती ज़्यादा सक्षम हो। इसके ज़रिए एक केवलरिफ़ धायम बंटक विशाल पैदा किया जात है, तकि मेहनतकर जनता को एकनुट

संघर्ष डेरेने से रोका जा सके और एक संसर्गीकतकारी राज कायम करने के नाम पर, जनतंत्र को कतार जा सके। भारतीय संघर्ष में इसी का नाम हिंदू राज है। भाजपा-आरएसएस के विमर्श की ध्वन-बंटक प्रकृति अब पूरी तरह से स्वतःस्पष्ट है। आज, जब देश की भ्रम शक्ति, खास तौर पर कुछ भ्रम शक्ति, बेरोजगारी के बोझ के नीचे टली हुई है और शिक्षा के बीच बेरोजगारी का अनुभव बहुत ही ज्यादा है, इस ज़रतत समस्या पर कहर के लिए देश के शासकों के पास एक राब्ट तक नहीं है। इसके बजाए वे गला पड़कर बालदेश में घुसपैश में बालदेश को इतरे हैं। विरुधना यह है कि चुनिके भाजपा खुद यह मानती है कि किसी देश का प्रसिरोध सफल धेरुत उत्पाद ही उसकी प्रगति का सही सूचक होता है और अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष के डिमांड पर बालदेश की प्रतिक्रिक आध इस समय भारत से ज्यादा है यानी उसे भारत से ज्यादा उतत माना जाना चाहिए। तब भाजपा जिस तरह की भारी घुमपैठ का दावा कर रही है, वैसी घुमपैठ एक कम ज्यादा उतत देश में, कम उतत देश में संभवित हो सकती है? उत्तराष्ट्रीय विचार के लोग पिछले कुछ समय से इसकी व्याख्या करने की कोशिश करते आ रहे है कि पिछले कुछ समय में भारत में हिंदुत्व का ऐसा उत्पार क्यों अथ है।

कराची हमले पर भारत-पाकिस्तान के बीच आरोप-प्रत्यारोप- आतंकवाद, सुरक्षा और क्षेत्रीय तनाव की नई चुनौती

पाकिस्तान के कराची शहर में सुल्हा प्रतिष्ठान पर हुए हमले के बाद एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान ने इस हमले के पीछे भारत का हाथ होने का आरोप लगाया है, जबकि भारत ने इन आरोपों को पूरी तरह तथ्यर और बेवैधानिक बतले हुए साबती से खारिज कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान को सलाह दी है कि वह दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय अपने देश में मौजूद आतंकवादी ढांचे के खिलाफ लेस कार्रवाई करे। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब पाकिस्तान के विभिन्न प्रांतों में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि देखी जा रही है और देश की आंतरिक सुरक्षा गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। भारत के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणवीर जायसवाल ने स्पष्ट कहा कि कराची की घटना को लेकर पाकिस्तान द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह आधारलेन हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देने के बजाय अपने देश में सक्रिय आतंकवादी संगठनों के खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई करनी चाहिए। भारत का यह भी कहना है कि पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद को अपनी राज नीति के एक साधन के रूप में इस्तेमाल करता रहा है और अब उसे इस प्रवृत्ति से बाहर निकलने की आवश्यकता है। कराची के गुलिसन-ए-नौहर इलाक़े में स्थित पाकिस्तान रेंजर्स के एक मुख्या शिविर पर हुए हमले में कम से कम तीन सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हुए। पाकिस्तान की सेना के जनसंपर्क विभाग के अनुसार हमलावरों ने पहले मुख्य द्वार पर बिम्पेड किया और उसके बाद सुरक्षा घरे को तोड़कर शिविर में घुसने का प्रयास किया। सुरक्षा बलों ने जबर्बो कार्रवाई करते हुए हमले को विफल करने का दावा किया। हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान के सूचना मंत्री मोहसिन नकवी ने दावा किया कि इस घटना के पीछे भारत का गुप्तधर्म प्राप्त आतंकवादी समूह है। हालांकि उन्होंने अपने आरोपों के समर्थन में कोई सांकेतिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। भारत ने इसी आधार पर इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बिना प्रमाण के लगाए गए ऐसे आरोप केवल बाह्यविक समस्या से घ्यान भटकने का प्रयास है। दरअसल, पाकिस्तान इस समय कई मोर्चों पर आतंकवादी हिंसा का सामना कर रहा है। कराची के अलावा कलुचिस्तान और खैबर पख्तुनख़ा में भी हाल के दिनों में कई हमले हुए हैं। कलुचिस्तान में सक्रिय संगठन क्लुच रिन्सेशन अर्मी ने निजारा स्थित एक सैन्य शिविर पर हमले को जिम्मेदारी ली है। इसी प्रकार जमत-उल-अहरार जैसे उग्रवादी संगठनों की गतिविधियां भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बन गई हैं। इन संगठनों का उद्देश्य अलग-अलग है, लेकिन इनकी टिंसक गतिविधियों ने पाकिस्तान को आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। पाकिस्तान लंबे समय से यह आरोप लगाता रहा है कि कलुचिस्तान और अन्य क्षेत्रों में सक्रिय फिरोही संगठनों को भारत का समर्थन प्राप्त है। दूसरी ओर भारत लगातार इन आरोपों से इनकार करता अथा है और कहता है कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक समस्याओं और सुरक्षा कमिलताओं का दोष भारत पर मढ़ने की कोशिश करता है। भारत का यह भी आरोप रहा है कि पाकिस्तान की धरती पर कई आतंकवादी संगठन खुले तौर पर सक्रिय हैं, जिनमें भारत सहित अन्य देशों में भी आतंकवादी गतिविधियों को अजाम दिया है।

बुद्धम् शरणम् गच्छामि-कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने बुद्ध विहार में किया दर्शन-पूजन

नई दिल्ली (ए.के.चौधरी)कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगे ने आज मंदिर मार्ग, दिल्ली,स्थित बुद्ध विहार में दर्शन-पूजन कि। इस अवसर पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी उनके साथ मौजूद रहे। पौधा भेंट कर किया स्वागत, देवेंद्र यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष श्री खरगे को पौधा भेंट कर उनका स्वागत किया। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए यह भेंट की गई। श्री खरगे ने दर्शन के बाद कहा, "बुद्धम् शरणम् गच्छामि। भगवान बुद्ध की कृपा हम सभी पर बनी रहे, यही प्रार्थना है।" उन्होंने देश में शांति, सद्भाव और करुणा के लिए प्रार्थना की।

देवेंद्र यादव ने कहा,दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बताया, दुः-आज हम सभी के

मार्गदर्शक आदरणीय कांग्रेस सुअवसर प्राप्त हुआ। भगवान विहार में बड़ी संख्या में कांग्रेस



अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगे जी के साथ मंदिर मार्ग स्थित बुद्ध विहार में दर्शन-पूजन का

बुद्ध के शांति और अहिंसा के संदेश आज के समय में और भी प्रासंगिक हैं। इस दौरान बुद्ध

कार्यकर्ता और स्थानीय श्रद्धालु भी मौजूद रहे। छया = सहित गौड़, दैनिक, सक्षम भारत

दिल्ली में इस दिन से होगी झमाझम बारिश, मानसून की एंट्री की तारीख तय, गर्मी से मिलेगी राहत

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में इस समय भीषण गर्मी और उमस ने लोगों का जीना दूभर कर रखा है। लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान और गर्म हवाओं के कारण दिन के समय बाहर निकलना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। हालांकि, मौसम विभाग (आईएमडी) के ताजा पूर्वानुमान ने लोगों को राहत की उम्मीद दी है। विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है और मानसून की गतिविधियां तेज होने के साथ दिल्ली-एनसीआर में बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, 29 और 30 जून को दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। इन दो दिनों के दौरान तेज धूप और उमस लोगों को परेशान करेगी। हालांकि, आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ शाम या रात के समय कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी, धूल भरी आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं। इससे तापमान में मामूली गिरावट महसूस हो सकती है, लेकिन व्यापक राहत मिलने की संभावना कम है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 1 जुलाई यानी बुधवार से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दिन से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश शुरू होने का अनुमान है। कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। बारिश का यह दौर गर्मी और उमस से राहत दिलाएगा तथा अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके बाद दिन का तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जिससे मौसम पहले की तुलना में काफी सुहावना हो जाएगा।मानसून को लेकर भी अच्छे खबर सामने आई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, अगले 5 से 6 दिनों के भीतर दक्षिण-पश्चिम मानसून के दिल्ली-एनसीआर में पूरी तरह सक्रिय होने की संभावना है। यदि मौजूदा परिस्थितियां अनुकूल बनी रहती हैं तो मानसून जल्द ही पूरे क्षेत्र को कवर कर लेगा। इसके बाद रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रह सकता है, जिससे भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी और वातावरण में ठंडक बढ़ेगी।

नई आपराधिक न्याय व्यवस्था लागू होने की दूसरी वर्षगांठ से पहले हरियाणा ने रचा इतिहास, 95 अंक हासिल कर बना नंबर-1 राज्य



पंचकूला । नए आपराधिक कानूनों के लागू होने की दूसरी वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर हरियाणा ने देशभर में एक नई मिसाल कायम की है। हरियाणा, नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निर्धारित 95 अंकों के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस उपलब्धि को राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय तथा आधुनिक तकनीक आधारित कार्यप्रणाली का परिणाम माना जा रहा है। इस मौके पर पुलिस

महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा कि राज्य सरकार ने नए आपराधिक कानूनों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करने, जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने तथा विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने पर विशेष ध्यान दिया। इसी का परिणाम है कि हरियाणा ने निर्धारित सभी प्रमुख मानकों को पूरा करते हुए 95 अंकों का लक्ष्य हासिल कर लिया। डीजीपी सिंघल ने आगे बताया कि इस

उपलब्धि के साथ हरियाणा ने यह संदेश दिया है कि न्याय व्यवस्था में सुधार और तकनीक आधारित पुलिसिंग के क्षेत्र में वह देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन से अपराधों की जांच में तेजी, पीड़ितों को समयबद्ध न्याय और न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। गौरतलब है कि 1 जुलाई 2024 से देशभर में नए आपराधिक कानून लागू किए गए थे, जिनके तहत भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह नए कानून लागू किए गए। इनका उद्देश्य न्याय प्रणाली को अधिक आधुनिक, पारदर्शी, तकनीक-सक्षम और नागरिक-केंद्रित बनाना है। हरियाणा की यह उपलब्धि न केवल राज्य के लिए गौरव का विषय है, बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणादायक उदाहरण मानी जा रही है। नए आपराधिक कानूनों की दूसरी वर्षगांठ से पहले मिली यह सफलता राज्य की प्रशासनिक दक्षता और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।

फरीदाबाद में कारोबारी ने किया सुसाइड, इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी कर पत्नी और ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप

फरीदाबाद । फरीदाबाद में बल्लभागढ़ के सेक्टर-3 में गारमेट की दुकान चलाने वाले 28 वर्षीय कारोबारी ने अपनी दुकान के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले कारोबारी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसने अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष पर मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वीडियो में लगाए गए आरोपों की भी जांच की जा रही है। मृतक की पहचान राउसिंग बोर्ड, सेक्टर-3 निवासी राहुल (28) के रूप में हुई है। वह सेक्टर-3 में गारमेट की दुकान चलाता था, जिसे उसने करीब चार महीने पहले शुरू किया था। पुलिस के अनुसार रविवार सुबह राहुल घर से अपनी मां से मिलकर दुकान पहुंचा था। कुछ देर बाद उसने दुकान के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बीके सिविल अस्पताल भेज दिया। परिजनों के अनुसार राहुल ने करीब



दो वर्ष पहले ज्योति नाम की युवती से लव मैरिज की थी। उनका आरोप है कि शादी के बाद पत्नी नहीं चाहती थी कि राहुल अपने माता-पिता के साथ रहे। इसी वजह से वह अलग रहने लगा था। झल ही में उसने अपनी नई गारमेट की दुकान भी शुरू की थी। मृतक के परिजन अमित ने आरोप लगाया कि राहुल काफी समय से अपनी पत्नी और उसके मायके पक्ष की प्रताड़ना से मानसिक रूप से परेशान था। उनका कहना है कि पत्नी ने राहुल के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया था, जिससे वह तनाव में रहने लगा था। परिजनों का यह भी आरोप

है कि राहुल को अपने माता-पिता से मिलने तक से रोका जाता था। आत्महत्या से पहले राहुल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उसने अपनी पत्नी ज्योति, सास बीना, ससुर बिट्टू और पत्नी की बहन नीतू पर गंभीर आरोप लगाए। वीडियो में राहुल ने दावा किया कि वह पत्नी के लिए घर के सभी काम झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करता था, इसके बावजूद उसके साथ मारपीट की जाती थी और उस पर झूठे मामले दर्ज कराए गए। उसने कहा कि वह लगातार मानसिक तनाव में था। वीडियो में राहुल ने यह भी कहा कि उसके इस कदम के लिए पत्नी और ससुराल पक्ष जिम्मेदार हैं तथा उन्हें कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए। साथ ही उसने अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति मां, बहन और भाइयों के नाम होने की बात भी कही। जांच अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है। वीडियो में लगाए गए आरोपों की सत्यता की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

आर्थिक रूप से कमजोर आईटीआई छात्रों को हर महीने 2000 रुपये... हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला

चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को आर्थिक मदद देकर तकनीकी शिक्षा की ओर आकर्षित करने की तैयारी में है। सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए दो हजार रुपये प्रतिमाह स्टैंडपेंड देने की पहल की है। बता दें कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक कारणों से कोई भी छात्र तकनीकी प्रशिक्षण बीच में न छोड़े। सरकार का मानना है कि आर्थिक सहयोग मिलने से आईटीआई में दाखिले बढ़ेंगे, विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित होगी और उद्योगों को प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध करने में मदद मिलेगी। जानकारी के अनुसार वर्ष 2026-27 के प्रवेश सत्र में हरियाणा के 377 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिले की प्रक्रिया चल रही है। इनमें 197 सरकारी और 180 निजी ITI शामिल हैं। इन संस्थानों में करीब एक लाख सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। विद्यार्थियों को 89 से अधिक इंजीनियरिंग और गैर-इंजीनियरिंग ट्रेडों में प्रशिक्षण का विकल्प मिलेगा,

जिनमें पारंपरिक ट्रेडों के साथ आधुनिक तकनीकी पाठ्यक्रम भी शामिल है। सरकार इस समय इस्कूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग (डोएसटी) पर विशेष जोर दे रही है। इस मॉडल में विद्यार्थियों को केवल कक्षा तक सीमित नहीं रखा जाता, बल्कि प्रशिक्षण के दौरान ही उद्योगों में व्यावहारिक अनुभव दिया जाता है। मशीनों पर काम करने, उत्पादन प्रक्रिया समझने, सुरक्षा मानकों का पालन करने और औद्योगिक कार्यप्रणाली सीखने का अवसर मिलने से प्रशिक्षण पूरा करने के बाद युवाओं को रोजगार के लिए अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ती। हरियाणा सरकार तकनीकी शिक्षा को सीधे उद्योगों की जरूरतों से जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। एक ओर आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को स्टैंडपेंड देकर प्रशिक्षण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पाठ्यक्रमों को उद्योग आधारित बनाया जा रहा है। इससे प्रशिक्षण पूरा करने वाले युवाओं के रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी और राज्य को कुशल कार्यबल भी मिलेगा।

हरियाणा के जल अधिकारों का सौदा नहीं होने देंगे, एक-एक बूंद की रक्षा के लिए लड़ेगी इनेलो - प्रो. संपत सिंह

(संवाददाता)

चंडीगढ़ । पूर्व वित्त मंत्री एवं इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय संरक्षक प्रो. संपत सिंह ने सोमवार को चंडीगढ़ स्थित पार्टी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर कहा कि इनेलो हमेशा हरियाणा के जल अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ई लड़ता रहा है और राज्य के यमुना जल में उसके वैधानिक हिस्से पर किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं करेगा। दिल्ली में आज बीजेपी ने जो हरियाणा और राजस्थान के बीच जल समझौता किया है इसका इनेलो पूरजोर विरोध करती है। दूसरी ओर, एस.वाई.एल. नहर का निर्माण भी सर्वोच्च न्यायालय के बार-बार निर्देशों के बावजूद अधूरा है, जिससे हरियाणा को लगातार जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां हरियाणा के पानी के मामले में एक हो चुकी है। कांग्रेस ने जैसे कुर्सी बचाने के लिए समझौता किया था उसी तर्ज पर आज बीजेपी सरकार ने राजस्थान को पानी देने का समझौता किया है। हरियाणा का पानी हरियाणा का है। इनेलो उसकी एक-



एक बूंद की रक्षा के लिए लड़ती रहेगी। उन्होंने कहा कि 12 मार्च, 1954 को तत्कालीन पंजाब और उत्तर प्रदेश के बीच हुए यमुना जल समझौते में पूर्वी एवं पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली के माध्यम से पंजाब के अधिकार को मान्यता दी गई थी। वर्ष 1966 में हरियाणा के गठन के बाद यह अधिकार हरियाणा को प्राप्त हुआ। कई दशकों तक लगभग 12 बीसीएम यमुना जल का उपयोग हुआ, जिसमें हरियाणा लगभग 8 बीसीएम तथा उत्तर प्रदेश लगभग 4 बीसीएम जल का उपयोग करता रहा। किन्तु 12 मई, 1994 को केंद्र सरकार की पहल पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली मुख्यमंत्रियों द्वारा किए गए नए समझौते के तहत हरियाणा का हिस्सा घटकर 5.730 बीसीएम कर दिया गया, जबकि उत्तर प्रदेश को 4.032 बीसीएम, राजस्थान को 1.119

बीसीएम, दिल्ली को 0.724 बीसीएम तथा हिमाचल प्रदेश को 0.378 बीसीएम आवंटित किया गया। इससे हरियाणा की हिस्सेदारी लगभग 67 प्रतिशत से घटकर 46 प्रतिशत रह गई। इससे पहले राजस्थान और दिल्ली को केवल अतिरिक्त उपलब्ध जल मानवीय आधार पर दिया जाता था, जिसे 1994 के समझौते ने स्थायी आवंटन का रूप दे दिया। प्रो. संपत सिंह ने कहा कि इसी समझौते में यमुना जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए रेणुका, किशाऊ तथा लखनवार-व्यासी बांधों के निर्माण का भी प्रावधान किया गया था, लेकिन तीन दशक से अधिक समय बीत जाने के बावजूद ये परियोजनाएं आज तक पूरी नहीं हो सकीं। उन्होंने कहा कि 1978 की भीषण बाढ़ के बाद 1989 में साहिबी, कृष्णावती एवं अन्य मौसमी नदियों के जल का सिंचाई के लिए उपयोग करने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने लगभग 69 करोड़ रुपये की लागत से मसाना जलाशय का निर्माण कराया। बाद में राजस्थान ने ऊपरी क्षेत्र में कच्चे बांध बनाकर प्राकृतिक जल प्रवाह को रोक दिया, जिससे हरियाणा की सिंचाई

क्षमता प्रभावित हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि इन पुराने विवादों का समाधान करने के बजाय वर्तमान भाजपा सरकार राजस्थान के साथ ऐसे नए समझौते कर रही है, जो हरियाणा के हितों को और कमजोर करते हैं। प्रो. संपत सिंह ने कहा कि 1994 में स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में यमुना जल समझौते के विरोध में इनेलो के सभी 17 विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इसे हरियाणा के जल अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी राजनीतिक दल द्वारा दिया गया सबसे बड़ा बलिदान बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही हरियाणा के वैध जल अधिकारों की प्रभावी रक्षा करने में विफल रही हैं। इनेलो लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीकों से हरियाणा के हितों की रक्षा के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगी। प्रो. संपत सिंह ने बताया कि शीघ्र ही चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में पार्टी की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें आगामी कदम का फैसला किया जाएगा।

हरियाणा-राजस्थान के लोगों की पानी से जुड़ी तीन दशक पुरानी समस्या हल, अब पेयजल की होगी निरंतर आपूर्ति

नई दिल्ली । केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में सोमवार को नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के संबंध में राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। शाह ने कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों को पानी से जुड़े लगभग तीन दशक पुरानी समस्या का समाधान हो गया है। यह समझौता प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए सहकारी संकेतक के भंन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। साथ ही यह

समझौता इस बात का भी उदाहरण है कि अगर राय सहकारी संकेतक की सोच को आगे बढ़ाएं तो तीन दशक पुरानी समस्या भी सफलता से सुलझ सकती है। इन मुद्दों पर बनी सहमति गृह मंत्री ने कहा कि इस समझौते के तहत जुलाई से अक्टूबर तक लगभग 580 घनमीटर पानी यमुना नहर से तीन भूमिगत पाइपलाइंस के जरिए राजस्थान तक पहुंचाया जाएगा। इन तीन पाइपलाइंस का व्यास 3.6 मीटर से भी अधिक है जिसके माध्यम से राजस्थान और हरियाणा रा्यों के लोगों

के लिए पेयजल की व्यवस्था होगी। यह समझौता दोनों रा्यों के लिए लाभदायक स्थिति का अंश उदाहरण है। समझौते में विनीत जियेदारी, लाभत सझीकरण, जल आवंटन और जल छोड़ने के प्रोटोकॉल और रखरखाव का बोझों से घटाना रखा गया है। इस वैज्ञानिक रूप से परिपूर्ण समझौते में बुनियादी ढांचे का संभलन, रखरखाव, निगरानी तंत्र, पारदर्शिता के उपायों और निरंतर समायोजन की प्रक्रिया को भी बहुत बढ़िया तरीके से समाहित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि



हरियाणा, राजस्थान और विशेषकर केंद्रीय जल आयोग ने इस समझौते का जो प्राकृष बनाया है वह आने वाले कई दशकों तक विवादहीन

समझौते के रूप में स्थापित होगा। हरियाणा-राजस्थान के इन जिलों को होना फायदा केंद्रीय जलराजि मंत्री सौअर पाटिल की अध्यक्षता में कुछ ही दिनें में इस समस्या का समाधान निकल गया है। इस समझौते के बाद राजस्थान के सोकर, चूरु और बुंदेल के साथ-साथ हरियाणा के पिकनी और पतेहवाड क्षेत्रों में भी पाने का पानी पहुंचाने की व्यवस्था हो जाएगी। शह ने कहा कि इस समझौते से राजस्थान और हरियाणा, विशेषकर राजस्थान, में पाने के पानी की समस्या के निराकरण में बहुत

सहायता मिलेगी। जो पानी किसी काम नहीं आ रहा था, इस समझौते के बाद अब वह पानी लोगों की पस बूझने और बड़े तकनीकों में संश्रित होकर भूजलस्तर बढ़ाने के काम आएगा। इस परियोजना का उद्देश्य पश्चिमी यमुना नहर से भूमिगत पाइपलाइन के जरिए राजस्थान के हिस्से का यमुना का पानी पहुंचाना है। इससे रूय, अगर यमुना बेसिन के दृतेभाल लायक सस्ती पानी के बचपने पर 1994 के समझौते के उक्त मिले पानी का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा। इस परियोजना से राजस्थान के सूखे और कम बारिश

वाले इलाकों में पाने के पानी की निरंतर आपूर्ति होगी। सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे लाखों लोगों को प्रशन्न होगा। यह समझौता केन्द्र सरकार और समझौते में शामिल राय सरकारों के एकतुट प्रयासों से परियोजना को सफल कर लागू करने की नींव रखने का काम करेगा। इस अनसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भननलाल शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नखन सिंह सैनी, केंद्रीय जलराजि मंत्री सौअर पाटिल और केन्द्र सरकार और राय सरकारों के जरिए अधिकारी उपस्थित थे।

अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ की खबरें निराधार- सेना ने दावों को किया खारिज

नई दिल्ली। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना द्वारा नए अतिक्रमण और सैन्य कैंप बनाने के दावों को फिरे में खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया और कुछ मोडिया रिपोर्टों में रफा किया जा रहा था कि चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा के भीतर घुसपैठ की है। सेना ने एक सरल आधिकारिक बयान जारी कर इन सभी खबरों को पूरी तरह गलत, धमक और बिना किसी आधार के बताया है। जलनैतिक निरंतरण रक्षा पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और भारतीय नयान मुस्ती से तैनात हैं। नाह वेलेफेर सोसाइटी का दावा और विवाद की शुरुआत यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी मुचमीसिरी जिले के सुदूर सीमावर्ती क्षेत्र ताकिमरा के एक स्थानीय संगठन नाह वेलेफेर सोसाइटी ने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन र्घीपा।



इस संगठन के अध्यक्ष केरु चाडर ने दावा किया था कि चीनी सेना पिछले 10 से 15 वर्षों में धीरे-धीरे भारतीय क्षेत्र में आगे बढ़ी है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया था कि चीन ने स्थानीय नाह आदिवासी समुदाय की पारंपरिक शिवार, पशु चरई और कृषि भूमि पर नियंत्रण कर लिया है।

दावे के मुताबिक, जो क्षेत्र साल 2020 तक पूरी तरह भारत के नियंत्रण में थे, वहां अब पोलार ने सड़के, पुल और स्थायी सैन्य शिविर बना लिए हैं। इस संगठन ने विशेष रूप से पांच संवेदनीय स्थानों, ओंथिंग, पॉन्गर, मयप, पोरंग झील और तिनदिंगता का नाम लिया था,

कहा-सीमा पर नियंत्रण में स्थित

जो स्थानीय लोगों के लिए पवित्र धार्मिक महत्व रखते हैं। स्थानीय नेताओं की चिंता स्थानीय संगठन के इस पत्र के सामने आते हैं राज्य में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर हालचल तेज हो गई। नाचो क्षेत्र के विधायक नाकाप नालो और पूर्व विधायक फंकंग बांगे ने इस विषय को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ बताया है। प्रशासनिक स्तर पर जांच की मांग की थी, ताकि सीमावर्ती नागरिकों का डर दूर हो सके। दूसरी तरफ, अरुणाचल प्रदेश करिष कमेटी ने भी केंद्र सरकार से इस संवेदनीय मामले पर तुरंत स्थिति स्पष्ट करने और सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। भारतीय सेना की मुस्ती बढ़ते विवाद को देखते हुए भारतीय

सुरक्षा प्रतिष्ठान ने तुरंत स्थिति साफ की। सैन्य सूत्रों के अनुसार, एलएसपी पर भारतीय सैनिक लगातार और बेहद मुस्ती से लांग-रेंज पैट्रोलिंग (एलआरपी) करते हैं। चीन के साथ सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर दोनों पक्ष अपनी-अपनी सीमाओं में काम करते हैं, लेकिन भारतीय क्षेत्र में किसी भी नए अतिक्रमण या अवैध चीनी कैंप बनाने की बात पूरी तरह झुठ और मनगढ़ंत है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार और केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने साफ किया है कि अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों, स्थानीयक पुलों और अग्रिम चौकियों के नेटवर्क को रिकॉर्ड गति से मजबूत किया है। सेना ने नागरिकों और मीडिया से अपील की है कि वे सीमा सुरक्षा जैसे संवेदनीय मामलों पर सोशल मीडिया पर चल रही अभूत्यों पर बिस्कुल भरोसा न करें।

अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हवाई हमलों की भारत ने की निंदा

नई दिल्ली । भारत ने योमवार को अफगानिस्तान पर पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई हमलों की निंदा की। पाकिस्तान ने 28 जून को सीमा पर सैन्य अभियान चलाते हुए अफगानिस्तान के भीतर कश्चित अलंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इस अभियान में हवाई और जमीनी दोनों तरह के हमले किए गए। अफगानिस्तान पर हुए इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिक हताहत हुए हैं। इन हमलों पर प्रतिक्रिया विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत, पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के क्षेत्र पर किए गए हवाई हमलों की कड़ी निंदा करता है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कई नागरिकों की मौत हुई है। अफगानिस्तान को यह खुली आक्रमक कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शंति एवं स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारत ने पाकिस्तान को जपकर लताड़ा भारत ने सीधे शब्दों में कहा, यह पाकिस्तान के लगातार दैर-निम्नप्रेशन रवैये को दर्शाता है। अपनी आंतरिक विफलताओं से



ज्मान भटकाने के लिए सीमाओं के पार हिंसक कार्रवाइयों का सहारा लेने की उसकी एक और निरापेक्ष कोशिश है। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत, अपने प्रियजनों को खोने वाले अफगान परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है, चापलों के सीध स्वस्थ होने की कामना करता है। अफगानिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपने अटूट समर्थन को दोहराता है। अफगानिस्तान पर लगातार हमले कर रहा है पाकिस्तान पिछले वर्ष से पाकिस्तान को और से

गैर-जिम्मेदाराना रवैया अफगानिस्तान को सीमा के भीतर कई सैन्य हमले किए जा चुके हैं। पाकिस्तान का कहना है कि उसके निशाने पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) और अन्य अलंकी संगठनों के ठिकाने थे। इस्लामाबाद लगातार अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर पाकिस्तान में होने वाले बातक हमलों के लिए जिम्मेवार टीटीपी के आतंकियों को शरण देने का आरोप लगाता रहा है। हालांकि, कानुन इन आरोपों से इनकार करता रहा है। इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तान की शुरुआती बमबारी में नागरिकों के हताहत होने का आरोप लगाते हुए अफगान तालिबान बलों ने बड़े पैमाने पर जमीनी नवाबी अभियान शुरू किया था। रिपोर्टों के मुताबिक, उन्होंने दूरदूरी रक्षा के पास पाकिस्तान की कई सीमा चौकियों और सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद पाकिस्तान ने बढ़े पैमाने पर हवाई और जमीनी नवाबी हमले किए।

निर्माणाधीन रिसॉर्ट में दीवार ढही, तीन मजदूरों की मौत; लंच टाइम ने टाली बढ़ी अनहोनी



जयपुर । जयपुर के चंदवाली खाना क्षेत्र स्थित तालापोड़ में निर्माणाधीन द अगस्टी प्लेस रिसॉर्ट में सोमवार को हुए भीषण हदसे में मृतकों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है। रिसॉर्ट के बेसमेंट में एसटीपी (सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट) का निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान अचानक एक दीवार धराशायर पिर गई, जिससे वहां काम कर रहे मजदूर मलबे के नीचे दब गए। हदसे में रिक्त, सफाता और रमजनों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य मजदूर घायल हो गए। घायलों का निम्न अस्पताल में इलाज जारी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हदसा दोषार के भोजन के समय हुआ। उस वक कई मजदूर खाना खाने के लिए साइट से बाहर गए हुए थे। प्रशासन का मानना है कि यदि हदसा कार्य के व्यस्त समय में होता तो नजदिक का आंकड़ और अधिक हो सकता था। घटना की सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस, पुलिस और प्रशासन की टीमें मौक पर पहुंची। मलबे में दबे लोगों की तलाश के लिए उत्खनन रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। सिविल डिफेंस की टीम अब भी सचें ऑपरेशन चला रही है, ताकि यह सुनिश्चित हो जा सके कि मलबे के नीचे कोई अन्य व्यक्ति फंसा न हो। प्रशासन हदसे के कारणों की जांच कर रहा है। साथ ही यह भी पड़ताल की जा रही है कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं। हदसे के बाद निर्माण स्थल पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

राममंदिर चोरी- 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत

अयोध्या। (वेबवार्ता) दुनिया भर में रामपूजों की आस्था को अक्षत पहुंचाने वाले राममंदिर चक्रवा चोरी के आठ आरोपियों को पुलिस को रिमांड नहीं मिली। सोमवार को वॉर्डन कोर्टमेंसिंग से सुनवाई हुई और आठों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इन आठों को पुलिस ने 26 जून को गिरफ्तार किया था। वॉर्डन कोर्टमेंसिंग पर सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश ध्रुवचर निवारण जज रजत वर्मा ने 13 जुलाई तक आठों आरोपितों की न्यायिक रिमांड अर्वाच बढ़ा दी है। अयोध्या में आधिकारिकों के बढ़ते अक्रोश को देखते हुए कोर्ट प्रशासन ने दो बजे वॉर्डन कोर्टमेंसिंग जल में सुनवाई का फैसला किया था। राम मंदिर दान गबन मामले में सोमवार को सभी आठों आरोपियों को एंटी करपशन कोर्ट में बचुअल माध्यम से पूर्ण हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत



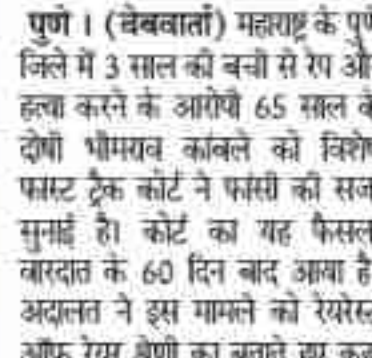
(जुडिशल करंटर्डी) 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। अदालत के आदेश के बाद सभी आरोपी फिलहाल जेल में ही रहेंगे। इस दौरान पुलिस ने किसी भी आरोपी की कार्टर्ड रिमांड की मांग अदालत से नहीं की। ऐसे में आरोपियों से पुलिस हिरासत में पूछताछ नहीं होगी और वे न्यायिक अभिरक्षा में ही रहेंगे। राम मंदिर दान गबन मामले को लेकर जांच एजेंसियां लगातार साया जुटाने में लगी हैं। मामले में आगे की कानूनी

कार्रवाई अदालत के निर्देशों और जांच की प्रगति के आधार पर होगी। यह मामला प्रदेश के नौरी, पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। श्रीराम मंदिर में चक्रवा चोरी के मामले में मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शिक्षात पर रसायनकार यादव टिन्नु सहित आठ लोगों के खिलाफ गुगवार को आठ नामजद व एक अन्य अज्ञात आरोपी के खिलाफ रामजन्मभूमि ध्वने में एचआईआर दर्ज कवाई गई। ये हैं चक्रवा चोरी के आरोपित

राम मंदिर में तेनात आरएमओ ब्रजुन देव हटाए गए, 1600 केमरों की निगरानी की थी जिम्मेदारी

अयोध्या । राम मंदिर चक्रवा चोरी प्रकरण में आरोपियों के घर छापेमारी और पूछताछ के बीच श्रीराम जन्मभूमि में 17 वर्षों से तेनात रांडेयो अपिरसन अधिकारी (आरएमओ) अनून देव को राम मंदिर से हटा दिया गया है। कार्टर्डिंग रूप में चक्रवा की गणना के दौरान लगे सीसीटीवी कैमरों के साथ पूरे मंदिर परिसर में लगे करीब 1600 कैमरों की निगरानी की जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी। ऐसे में एसआईटी ने पुलिस यह पता लगा रही है कि इनकी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद कार्टर्डिंग रूपों के चक्रवा की चोरी कैसे होती रही और निगरानी तंत्र कहां नाकाम रहा। मुजों के मुताबिक अनून देव वर्ष 2009 से लगातार अयोध्या में तेनात थे। इस दौरान कई बार उनके तबादले के आदेश हुए, लेकिन हर बार किसी न किसी स्तर पर रुक गए। हाल में लखनऊ तबादले का आदेश भी मिला है। एसआईटी अब यह भी खंगल रही है कि आखिर उनके तबादले बार-बार किसके स्तर से रुकवाए गए और एक ही जिले में 17 वर्ष तक तेनाती को बजाह क्या रही। अनुकल्प मिश्र, लखनऊ मिश्र, मनीष यादव, राजेश पांडे, रामांकर यादव उर्फ टिन्नु, अविनाश शुक्ल, करणेश पांडेय और सुभाष श्रीवास्तव। एसआईटी ने रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपताराय के चालक रहे

रेप-मर्डर के दोषी को फांसी की सजा सुनाई



पुणे । (वेबवार्ता) महाराष्ट्र के पुणे जिले में 3 साल की बच्ची से रेप और हत्या करने के आरोपी 65 साल के दोषी भीमराव काबले को विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट का यह फैसला वारदात के 60 दिन बाद आया है। अदालत ने इस मामले को रेपरेट ऑफ ररर श्रेणी का बताते हुए कहा कि आरोपी का कृप बेहद वरर, अमाननीय और बर्बर था। सोमवार सुनह 11 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपी को अदालत में पैर किया गया था। काबले पेरो से मजदूर है। वह 7 बजों का पिता और 11 बच्चों के दादा हैं। यह घटना 1 मई को पुणे जिले के नसरपुर गांव में हुई थी। बच्ची गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के घर आई हुई थी। दोपहर 3 से 4 बजे के बीच काबले ने उसे खाने-पाने की चीजों और गाय का

नक्वाना बछड़ा दिखाया का लालच देकर बहला-फुसलाकर उसने साथ ले गया। इसके बाद वह उसे मयेशिया के तबले के पास बने एक रोड में ले गया, जहाँ उसने उसके साथ रेप किया और फिर पथर से मिर कुच्छकर उसकी हत्या कर दी।

मध्य प्रदेश भूमि विवाद - कांग्रेस ने सीएम मोहन यादव पर लगाए आरोप, कहा- जनता कर रही जवाब का इंतजार



नई दिल्ली । कांग्रेस ने सोमवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर भूमि घोटाले का मास्टरप्लान होने का आरोप लगाया और दावा किया कि व्वांटिक फायदे के लिए इस घोटाले को अंजाम दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जखबदेवी तय करने के लिए वह मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग जारी रखेगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा पोस्ट में लिखा, इसमें कोई रुक नहीं है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, व्वांसगत फायदे के लिए

किए गए इस बड़े भूमि घोटाले के मास्टरप्लान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुख्यमंत्री मोहन यादव को जखबदेह ठहरने के लिए उनके इस्तीफे की मांग जारी रखेगी, क्योंकि वहाँ एकमात्र तरीका है जिससे उन्को जखबदेही सुनिश्चित हो जा सकती है। जयराम रमेश को यह टिप्पणी मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जेतु पटवारी की उस पोस्ट के बाद आई, जिसमें उन्होंने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाया था। पटवारी

ने एक्स पर लिखा, मुख्यमंत्री जी, समय तेजी से बीत रहा है, लेकिन आफ्नी चुप्पी अब भी बरकरार है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आफ्नी जनता के सवालों का जवाब देने के लिए तीन दिन का समय दिया था। दूसरा दिन भी बीत चुका है, लेकिन पूरे प्रदेश की निगाहें अब भी आप पर टिकी हुई हैं। पटवारी ने कहा, मंत्री बोल चुके हैं, संगठन अपनी बात रख चुका है और आधिकारिक स्पष्टीकरण भी जारी हो चुके हैं, लेकिन जनता जानना चाहती है कि मुख्यमंत्री खुद कब बोलेंगे? उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, अब केवल एक दिन बाकी है। मध्य प्रदेश की जनता आफके जवाब का इंतजार कर रही है। अगर तब भी आफ्नी चुप्पी नहीं टूटी तो कांग्रेस 30 जून को धाराचार सभा आयोजित करेगी और जनता के साथ जखब दो अभियान शुरू करेगी। सबल पृष्ठन जनता का अधिकार है। अब फैसला आपपर है।

रिफॉर्मस पर दिल्ली में मंथन- पीएम मोदी ने क्यों बुलाई सभी सचिवों की बैठक



नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी मोदी ने मंगलवार को केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिवों की बैठक बुलाई है। सरकार का पूरा जोर देश में इन ऑफ लिंक्ड यानी जोनन को आसान बनाने और इन ऑफ लूज बिजनेस यानी व्यापार को मुगम बनाने पर है। मुजों के मुताबिक, बैठक में कई सचिव अपने-अपने मंत्रालयों के कामकाज, सुधारों की प्रगति और जन-केंद्रित कदमों का पूरा ज्वाय पेश करेंगे। क्या भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे होने तक विकसित देश बन पाएगा? पीएम मोदी पहले से साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य तय कर चुके हैं। इसी कड़ी में अब नेकस्ट-जेन रिफॉर्मस यानी अगली पीढ़ी के सुधारों की समीक्षा की



जाएगी। पीएम मोदी का साफ निर्देश है कि सभी सचिव सामन और डिलीवरी पर ध्यान केंद्रित करें। सरकारी कामों में, विशेषकर अप जनता से जुड़े मामलों में कोई खिनाई या पेडेसी नहीं होनी चाहिए। आर्थिक तरक्की और भावी रोडमैप की चुनौतियां

क्या देश को यह तेज आर्थिक रफतार आगे भी बरकरार रहेगी? इस उच्च स्तरीय बैठक में विनीत वर्ष 2025-26 के 7.7 प्रतिशत की जीडीपी विकास दर और जीवों तिमाही के 7.8 प्रतिशत के आंकड़ों पर भी गंभीर चर्चा होने की उम्मीद है। मजबूत बुद्धि मांग और सरकारी खर्च के दम पर जनवरी-मार्च तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने अनुमानों को पीछे छोड़ दिया है। एक साल पहले विकास दर 7 प्रतिशत थी, जो अब बरकरार 7.8 प्रतिशत हो गई है। इसी तरह, पूरे साल की विकास दर भी वित्त वर्ष 2025 में 7.1 प्रतिशत से बढ़कर अब 7.7 प्रतिशत पर पहुंच गई है। बैठक में क्या होगा खास? विकसित भारत का लक्ष्य- साल 2047 तक देश को विकसित बनाने

के लिए खाका तैयार करना। रिफॉर्म एक्साइस की रफतार- पिछले 10 साल में हुए व्यवस्थागत बदलावों को और आगे बढ़ाना। जीडीपी में रिकॉर्ड उछाल- वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज हुई 7.7फोसदी की मजबूत आर्थिक विकास दर की समीक्षा। जीरो पेडेसी पर जोर- जनता से जुड़े सरकारी कामों और फाइलों को बिना देरी निपटाने का सख्त निर्देश। सुकाओं के लिए अवसर- देश में रोजगार और युवाओं के लिए नए रफते खोलने पर विशेष फोकस। प्रशासनिक दिग्गजों की मौजूदगी इस पूरी काबयद को जमीन पर कौन उतारेगा? प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि मंत्रियों और अधिकारियों का एकमात्र उद्देश्य जनता के जीवन का आमजदक बनाना होना चाहिए।

दिल्ली में नई ईवी पॉलिसे की मंजूरी, एक जुलाई से होगी लागू

नई दिल्ली । दिल्ली सरकार ने सोमवार को नई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पॉलिसे को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संविधान में अव्योक्त प्रेरणाओं में कहा कि यह नीति दिल्ली की वर्षों पुरानी प्रवृत्त और परंपरागत संबंधों को सुनिश्चित के समायोजन की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि उपराज्यपाल की संसुति के बाद यह नीति एक जुलाई से लागू होगी और 31 अगस्त 2031

तक प्रभावी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई ईवी पॉलिसे में आम लोगों को करीब 15 हजार करोड़ रुपये का लाभ मिलने का अनुमान है। सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी और प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की है, ताकि अधिक से अधिक लोग इलेक्ट्रिक वाहन अपनाएं। उन्होंने कहा कि दोपहिया, चारपहिया, तिपहिया, ट्रक और त्रामोण परिवहन वाहनों को भी

इस नीति के त्वाये में शामिल किया गया है। प्रेरणा की शुरुआत करते हुए शिक्षा मंत्री अशीष सुद ने बताया कि यूपी ऑफ मिनिस्टर्स ने सोमवार को नई ईवी पॉलिसे का मसौदा मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे बाद में मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि इस नीति को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न हितधारकों के साथ कई दौर की बैठकों की गईं। परिवहन विभाग की

सचिव निहारिका ने बताया कि कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद पॉलिसे का मसौदा उपराज्यपाल को भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि मंगलवार तक उनकी मंजूरी भी मिल जाएगी। नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों के लिए 30 हजार से 50 हजार रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदने पर एक लाख रुपये तथा त्रामोण सेवा वाहनों के

लिए 20 हजार रुपये का सब्सिडी इस्तेमाल मिलेगा। सरकार ने चरणबद्ध तरीके से पारंपरिक ईंधन वाले वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगाने का भी नियंत्रण लिया है। इसके तहत वर्ष एक जनवरी 2027 से सन तीनपहिया और वर्ष अगस्त 2028 से सन दोपहिया वाहनों का पंजीकरण केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के रूप में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक

स्थानों पर बड़े पैमाने पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। साथ ही डिजिटल के साथ मिलकर रा्यों में ईवी चार्जिंग के लिए अलग मोटर उल्लेख करने की व्यवस्था भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस नीति के तहत खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहन तीन वर्ष तक दिल्ली के बाहर बेचे नहीं जा सकेंगे। परिवहन मंत्री मजिंदर सिंह मिरसा ने कहा कि नई ईवी पॉलिसे से राजधानी में वायु

प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। जहाँ स्वस्थ मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने लोगों से इस नीति को अपनाने की अपील करते हुए कहा कि परिवहन विभाग ने इसी तैयार करने में व्यपक मेहनत की है और इसके बेहतर परिणाम सामने आएंगे। परिवहन विभाग को इस नीति के क्रियान्वयन का नेज़र विभाग बनाया गया है।

सब्सिडी नई ईवी पॉलिसे में इलेक्ट्रिक दोपहिया, ऑटो और मालवाहक वाहनों के लिए चरणबद्ध खरीद सब्सिडी का प्रत्यक्ष किया गया है। दोपहिया वाहन पर पहले वर्ष अधिकतम 30 हजार रुपये, इलेक्ट्रिक ऑटो पर 50 हजार रुपये और एन। श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रक पर पहले वर्ष एक लाख रुपये तक की खरीद सब्सिडी मिलेगी।